बेंगलुरु फैक्ट्री से आईफोन 17 उत्पादन शुरू

फॉक्सकॉन ने चीन से बाहर भारत को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया

नई दिल्ली, 18 अगस्त.ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज और एप्पल की प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन ने अपने नए बेंगलुरु फैक्ट्री में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है. यह इस फैक्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और लगभग 2.8 बिलियन डॉलर (लगभग 25,000 करोड़ रुपए) के निवेश से स्थापित की गई है.

देवनहल्ली स्थित बेंगलुरु यूनिट अब फॉक्सकॉन के चेन्नई प्लांट के साथ-साथ चालू हो गई है, जहां आईफोन 17 का उत्पादन भी चल रहा है. यह पिछले साल लगभग इसी समय-सीमा में आईफोन 16 सीरीज के स्थानीय उत्पादन के बाद है, जो इसके वैश्विक और भारत में लॉन्च से पहले था.

हालांकि, एप्पल या फॉक्सकॉन ने अभी तक इस घटनाक्रम पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. इस साल की शुरुआत में कई चीनी इंजीनियरों के अचानक चले जाने के बाद नई यूनिट को कुछ समय के लिए झटका लगा था, लेकिन फॉक्सकॉन ने इस कमी को पूरा करने के लिए ताइवान और दूसरे स्थानों से विशेषज्ञों को लाने में कामयाबी हासिल की है. दरअसल, एप्पल भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने पर बड़ा दांव लगा रहा है. कंपनी द्वारा इस वर्ष आईफोन उत्पादन को 6 करोड़ यूनिट तक बढ़ाने की उम्मीद है, जबकि 2024-25 में यह 3.5-4 करोड़ यूनिट था. वहीं, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में, एप्पल ने भारत में 60 प्रतिशत अधिक आईफोन असेंबल किए, जिनकी अनुमानित कीमत 22 अरब डॉलर है.

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में कंपनी की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया.

> एसएंडपी ग्लोबल के एक विश्लेषण से पता चलता है कि 2024 में अमेरिका में आईफोन की बिक्री 75.9 मिलियन यूनिट तक पंहुच गई. मार्च 2025 तक भारत से निर्यात 3.1 मिलियन यूनिट होने के साथ, इस मांग को पूरा करने के लिए एप्पल को या तो अपनी क्षमता बढ़ाकर शिपमेंट दोगुना करना होगा या घरेलू बाजार के लिए अधिक डिवाइस भेजने होंगे. इस बीच, भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है. 2025 की पहली छमाही में आपूर्ति सालाना 21.5 प्रतिशत बढ़कर 5.9 मिलियन यूनिट हो गई, जिसमें आईफोन 16 सबसे अधिक शिप किए जाने वाले मॉडल के रूप में उभरा.

निखिल का 137.5 करोड़ निवेश गोल्डी सोलर में

मुंबई, 18 अगस्त. ब्रोकरेज कंपनी जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत ने सोमवार को सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता गोल्डी सोलर में 137.5 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की. अभी यह पता नहीं चल सका है कि इस निवेश के साथ उन्हें गोल्डी सोलर में कितनी हिस्सेदारी हासिल हुई. एक बयान में कहा गया कि गुजरात स्थित गोल्डी सोलर इस नए निवेश का उपयोग विस्तार गतिविधियों के लिए करेगी.

कामत ने कहा, ''भारत में नवीकरणीय ऊर्जा एक विशाल क्षेत्र है, और हमारे घरेलू क्षेत्र में ही वैश्विक स्तर की कंपनियां बनाने का बड़ा अवसर है.'' बयान में कहा गया कि पिछले वर्ष गोल्डी की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता तीन गीगावाट से बढ़कर 14.7 गीगावाट हो गई है.

जीएसटी कटौती से ऑटो उद्योग को राहत : रिपोर्ट

बड़ी कारों की कीमत 3-5 प्रतिशत तक कम हो सकती है

मारुति सुजुकी को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा

नई दिल्ली 18 अगस्त. एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च ने सोमवार को कहा कि आगामी वस्तु एवं सेवा कर में कटौती से भारत में दीर्घकालिक ऑटो मांग और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा. सरकार भारत में जीएसटी स्लैब को सरल बनाने पर विचार कर रही है और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है और ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दरों के ऊपर लगाया गया सेस भी समाप्त किया जा सकता है.

जीएसटी संग्रह की बात करें तो यात्री वाहन (पीवी) 14-15 अरब डॉलर और दोपहिया वाहन 5 अरब डॉलर का जीएसटी संग्रह करते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, अभी तक इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, इसलिए हम विभिन्न परिदृश्यों पर विचार कर रहे हैं और विभिन्न जीएसटी दरों के प्रति कंपनी-स्तरीय जोखिम और निवेशकों के लिए ओईएम में सापेक्ष लाभ का मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा पर प्रकाश डाल रहे हैं.

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वर्तमान में पीवी में, जीएसटी 29 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है क्योंकि वाहन के आकार (सीसी और लंबाई) के आधार पर जीएसटी के ऊपर सेस लगाया जाता है. नई व्यवस्था में, सरकार छोटी कारों पर कर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर सकती है और बड़ी कारों के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू कर सकती है और जीएसटी के ऊपर सेस को समाप्त कर सकती है.

इसका मतलब है कि छोटी कारों की कीमतों में 8 प्रतिशत और बड़ी कारों की कीमतों में 3-5 प्रतिशत की कमी आ सकती है.

> एमएंडएम के लिए, प्रस्तावित जीएसटी कटौती भी एक अनुकूल स्थिति है, हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों में ज्यादा निवेश के कारण यह अपेक्षाकृत नुकसानदेह स्थिति में है. कारों के आकार के आधार पर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की एक समान कटौती और बाकी सब कुछ समान रहने की स्थिति एक सरलीकृत व्यवस्था है, हालांकि एक कम संभावना वाली स्थिति यह है कि मूल जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाए और वाहनों के आकार के आधार पर कारों पर लगाया गया शेष सेस समान रहे.

इंडिगो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लांच

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (वार्ता) देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है.

कंपनी ने सोमवार को बताया कि ग्राहकों को एक ही एप्लिकेशन में मास्टरकार्ड और रुपे दोनों नेटवर्कों का कार्ड जारी किया जायेगा. इसमें यात्रा संबंधी अन्य सुविधाओं के साथ इंडिगो का टिकट बुक कराने पर ज्यादा रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेंगे.

कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ज्वाइनिंग फीस 4,999 रुपये होगी. इसमें ग्राहकों को 5,000 रुपये का इंडिगो ब्लूचिप्स (रिवॉर्ड प्वाइंट) और पूरक 6ई ईट्स (खाने का) वाउचर मिलेगा.

ग्राहक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक लाख रुपये की सावधि जमा कराकर भी बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कार्ड एक्टिवेट करने के 90 दिन के भीतर एक लाख रुपये खर्च करने पर 3,000 अतिरिक्त ब्लूचिप्स मिलेंगे. इंडिगो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिये इंडिगो के टिकट बुक कराने के लिए खर्च किये गये हर 100 रुपये पर 22 ब्लूचिप्स तक मिलेंगे.

कंपनी ने बताया कि विदेशी मुद्रा में खर्च करने पर विनिमय दर कम होगा. साथ ही इंडिगो के टिकट रद्द कराने पर कवर, यात्रा बीमा और लाइफस्टाइल से जुड़े दूसरे लाभ भी होंगे.

जीएसटी में कटौती से बढ़ेगी एसी की मांग

नयी दिल्ली, 18 अगस्त.एयर कंडीशनर (एसी) पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को मौजूदा 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के सरकार के प्रस्ताव से उपकरण विनिर्माताओं को आगामी त्योहारों के दौरान अच्छी बिक्री की उम्मीद है.इससे विभिन्न मॉडल के आधार पर एयर कंडीशनर (एसी) की कीमतें 1,500 रुपये से 2,500 रुपये तक कम हो जाएंगी. सरकार द्वारा हाल ही में आयकर में कटौती और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में संशोधन के बाद कीमतों में यह कटौती होने जा रही है. अब इस कदम से न केवल एसी तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि 'प्रीमियम एसी' की मांग भी बढ़ेगी जहां लोग लागत लाभ के कारण ऊर्जा-कुशल मॉडल खरीदेंगे.

यूपीआई लेनदेन पर शुल्क का प्रस्ताव नहीं

जुलाई 2025 में 1,946 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए

डिजिटल भुगतान लेनदेन 22,831 करोड़ तक पहुँच गए

नई दिल्ली ,18 अगस्त. केंद्र सरकार ने सोमवार को दोहराया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित डिजिटल भुगतान पर किसी प्रकार का लेनदेन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

यह बयान डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और इसे उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10 के तहत, यूपीआई जैसे

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता शुल्क नहीं लगाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एसयू के तहत शुल्क-मुक्त भुगतान माध्यमों के रूप में अधिसूचित किया है. यूपीआई की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक प्रोत्साहन योजना लागू की.

यूपीआई लेनदेन में रिकॉर्ड वृद्धि

यूपीआई ने डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है. वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ लेनदेन से शुरू होकर, वित्त वर्ष 2024-25 में यह 18,587 करोड़ तक पहुंच गया, जो 114 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाता है.

लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में भारत ने मारी लंबी छलांग

2741 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मार्च 2025 तक चालू

2027 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका

नई दिल्ली 18 अगस्त. विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद की पुष्टि की है, जिसके तहत देश 2023 के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है. यह 2018 की पिछली रैंकिंग के बाद से छह स्थानों का उल्लेखनीय सुधार है.

रैंकिंग में यह तेज उछाल भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उसे सुव्यवस्थित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है. भारत 2030 तक दुनिया के शीर्ष 25 लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखता है, जिसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 10त्न से नीचे लाना है. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने हाल ही में वर्ष 2024-25 में 145.5 मिलियन टन के रिकॉर्ड माल परिवहन की सूचना दी है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि मुख्यत: वर्तमान में जारी निवेश और मज़बूत सरकारी नीतियों के कारण संभव हुई है. इसी अवधि के दौरान चालू राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या भी 24 से बढ़कर 29 हो गई है.

जुलाई 2017 में, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास की देखरेख के लिए वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अलग लॉजिस्टिक्स इकाई का गठन किया गया था. लॉजिस्टिक्स उद्योग आर्थिक विकास और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन्वेंट्री, परिवहन, भंडारण, वेयरहाउसिंग और वितरण का प्रबंधन करके, उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़कर, विनिर्माण, खुदरा, ई-कॉमर्स और सेवाओं को बढ़ावा देता है. गौरतलब हो, जुलाई 2017 में, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास की देखरेख के लिए वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अलग लॉजिस्टिक्स इकाई का गठन किया गया था. लॉजिस्टिक्स उद्योग आर्थिक विकास और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन्वेंट्री, परिवहन, भंडारण, वेयरहाउसिंग और वितरण का प्रबंधन करके, उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़कर, विनिर्माण, खुदरा, ई-कॉमर्स और सेवाओं को बढ़ावा देता है. गौरतलब हो, जुलाई 2017 में, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास की देखरेख के लिए वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अलग लॉजिस्टिक्स इकाई का गठन किया गया था. लॉजिस्टिक्स उद्योग आर्थिक विकास और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन्वेंट्री, परिवहन, भंडारण, वेयरहाउसिंग और वितरण का प्रबंधन करके, उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़कर, विनिर्माण, खुदरा, ई-कॉमर्स और सेवाओं को बढ़ावा देता है. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) को एनएमपी के पूरक के रूप में सितंबर 2022 में शुरू किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करके एक अधिक निर्बाध लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का निर्माण करना है.

पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान : सरकार ने अक्टूबर 2021 में विभिन्न परिवहन साधनों को एक समन्वित नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए इसे लॉन्च किया था. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योजना भारत की मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बदलने के उद्देश्य से तेज, निर्बाध और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे और रसद विकास रणनीति पर केंद्रित है. समुद्री अमृत काल विजन 2047, नीली अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप, भारत के समुद्री क्षेत्र में बदलाव के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप प्रस्तुत करता है.

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

ज्ञात हो, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. सेवा, विनिर्माण और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों ने 2021 और 2022 में महामारी के बाद भारत की मजबूत रिकवरी का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप इन दो वर्षों में 15.3त्न की वृद्धि हुई. तब से भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है, जिसकी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2024-2025 में 6.5त्न रहने का अनुमान है. वहीं, आज मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं का अर्थ है, कल एक मजबूत और अधिक लचीला भारत. बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटलीकरण पर सरकार के प्रयासों ने विकास को और तेज किया है. हाइड्रोजन हब जैसी हरित पहलों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. विजन का उद्देश्य तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्री कौशल विकास को मजबूत करना और भारत को जहाज निर्माण एवं मरम्मत के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है.

भाजपा से जुड़े संगठनों के पुनर्गठन में देरी

पटना. बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को नेतृत्व संभालते हुए एक वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अभी तक पार्टी के अनुषांगिक संगठन का पुनर्गठन नहीं हुआ. सात मोर्चा के साथ ही विभिन्न प्रकोष्ठ, प्रकल्प एवं विभाग सम्मिलित हैं. विधानसभा चुनाव सामने है. ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है. विशेषकर संगठनात्मक कार्य में वर्षों से बगैर किसी पद के स्वयं को समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं की पीड़ा छलकने लगी है.

NAME CORRECTION

It is for general information that I, PRABHUDAYAL SHARMA S/o Shankar Lal Sharma R/o Sohagpur Narmadapuram Hoshangabad Madhya Pradesh-461771, declare that name of mine has been wrongly written as PD Sharma in my minor Son namely Utkarsh Sharma age-17 years in his class-10th marksheet cum certificate educational documents, The actual name of mine is Prabhudayal Sharma, Which may be amended accordingly.

R.N.- 55719

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जगदीश दाहिया उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम शिवपुर्वा बाणगंगा टोला रीवा (म.प्र.) सूचना यह कि मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में कोमल कोटवार दर्ज है और स्कूल में रावेन्द्र दाहिया है. अत: अब से वह सभी शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यों में रावेन्द्र दाहिया के नाम से ही जाना व पहचाना जाएगा.

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल

क्रमांक 4054/ राजस्व/ भोविप्रा / 2025 भोपाल, दि.11/8/2025

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण साकेत नगर योजना में स्थित भूखण्ड क्र.-198 सेक्टर-2बी श्रीमती गोकुल धनगर पत्नी श्री आर.पी. धनगर के नाम पर आवंटित है. उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 14/01/1996 में निष्पादित की गई. आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड हेतु श्री दीपक गौड़ आ. श्री आर.आर. गौड़ को मुख्तारआम नियुक्त कर भूखण्ड पर प्रकोष्ठों का निर्माण कर पृथक-पृथक व्यक्तियों को विक्रय कर रजिस्ट्रियां की गई जिसमें प्रकोष्ठ क्र. एफ-04 का विक्रय श्री सपन सिन्हा आ. श्री एस.के. सिन्हा को विक्रय कर दिनांक 27/12/2000 को रजिस्ट्री कर दी गई. उक्त पंजीकृत रजिस्ट्री के आधार पर श्री सपन सिन्हा द्वारा अपने नाम पर प्रकोष्ठ का नामांतरण चाहा गया है.

उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/ दावा प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा.

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

R.N.- 55718

दूरसंचार लाभ में 14% तक बढ़ोतरी

बढ़ती डाटा खपत और 5जी विस्तार से कंपनियों को फायदा

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (वार्ता) बाजार अध्ययन एवं साख निर्धारण कंपनी क्रिसिल ने सोमवार को कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश की दूरसंचार कंपनियों का औसत परिचालन लाभ 12 से 14 प्रतिशत तक बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंचने की उम्मीद है.

क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि डाटा उपभोग बढ़ने से दूरसंचार कंपनियों का प्रति व्यक्ति औसत राजस्व बढ़ रहा है. साथ ही 5जी नेटवर्क के लिए ढांचागत विस्तार का काम पूरा होने के बाद अब पूँजीगत व्यय में भी कमी आने से कंपनियों का परिचालन लाभ उच्च स्तर पर बना रहेगा. एजेंसी ने जिन तीन कंपनियों के आंकड़ों का अध्ययन किया है, पिछले वित्त वर्ष में उनका परिचालन लाभ करीब 17 प्रतिशत रहा था. क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक आनंद कुलकर्णी ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों का प्रति उपभोक्ता

औसत राजस्व पिछले वित्त वर्ष के 205 रुपये से बढ़कर 220 रुपये से 225 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. इसमें बड़ा योगदान 5जी नेटवर्क के विस्तार का है जिससे डाटा का उपभोग बढ़ रहा है. मार्च 2025 में 5जी नेटवर्क कवरेज 35 प्रतिशत था जिसके अगले साल मार्च तक बढ़कर 45 से 47 प्रतिशत तक होने की संभावना है.

अपने को बदल रही हैं मायावती

लखनऊ. बहुजन समाज पार्टी की लगातार खराब होती स्थिति का नतीजा यह है कि पार्टी सुप्रीमो यानी बहनजी मायावती बदल रही हैं.

यह खबर लखनऊ से है. खबर है कि मायावती ने इस बार नौ अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पार्टी के अनेक नेताओं को राखी बांधी. बताया जा रहा है कि वे पार्टी कार्यालय में काफी देर तक मौजूद रहीं और वहां आने वाले हर नेता को उन्होंने राखी बांधी. हालांकि सभी नेताओं को इसकी तस्वीर डालने की मनाही थी. फिर भी पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने फोटो सोशल मीडिया में डाली. उन्होंने मायावती को बहन और प्रेरणास्रोत बताते हुए तस्वीर पोस्ट की. इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही यह बात सार्वजनिक हुई कि मायावती ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती निर्मला कछवाय (Smt. Nirmala Kachhway) पत्नी श्री आनंद कुमार कछवाय आयु-60 वर्ष, मेरे सर्विस रिकॉर्ड मे मेरा नाम श्रीमती निर्मला आनंद कुशवाह (Smt. Nirmala Anand Kushwah) दर्ज है जो कि त्रुटिवश दर्ज हो गया है। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम श्रीमती निर्मला कछवाय (Smt. Nirmala Kachhway) मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ मेरा यही नाम प्रचलन में है।

प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती निर्मला कछवाय (Smt. Nirmala Kachhway) के नाम से जाना पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

आवेदिका
श्रीमती निर्मला कछवाय
(Smt. Nirmala Kachhway)
पता-30, दाता कॉलोनी एयरपोर्ट रोड, बैरागढ़
तह. हुजूर जिला भोपाल म.प्र. 462030,

विशेष | **वन पर्सन, वन पोस्ट का फॉर्मूला तोड़ सौंपे दो पद; क्या है दीदी की स्ट्रैटजी?**

ममता ने भतीजे को ही क्यों किया आगे

कोलकाता. राजनीति की बिसात पर कब कौन सी चाल चलनी है, कब किसे आगे करना है और किसे पीछे, कब आक्रामक होना है और कब शांत, अनुभवी नेता ये सारे दांव भली-भांति जानते हैं. मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भी ऐसी ही अनुभवी व मंझी हुई नेता हैं. वर्ष 2026 का विधानसभा चुनाव नजदीक है.

ममता को 15 वर्षों के व्यवस्था विरोधी कारकों के साथ चुनाव लड़ना है. ऐसे में सांगठनिक एकजुटता जरूरी है.

इसीलिए वह एक-एक कर चालें चल रही हैं ताकि चौथी बार जीत की राह में मुश्किलें न आएं. इन्हीं में से एक चाल है, अपने पार्टी महासचिव व सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को वरिष्ठ नेता सुदीप बंद्योपाध्याय की जगह लोकसभा में तृणमूल संसदीय दल का नेता बनाना.

ममता ने अपने भतीजे को आगे कर बड़ी चाल चली है ताकि एक तीर से कई निशाने साधे जा सकें. अभिषेक को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाना अचानक लिया गया निर्णय नहीं है. वर्ष 2021 में प्रशांत किशोर के चुनाव प्रबंधन में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी में अभिषेक बनर्जी का कद काफी बढ़ गया था, क्योंकि प्रशांत किशोर को वे ही रणनीति बनाने के लिए बंगाल लाए थे. उस जीत के बाद अभिषेक ने पार्टी में 'एक व्यक्ति, एक पद' और चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा तय करने की योजना बनाई थी, ताकि तृणमूल को नए कलेवर में लाया जा सके और युवाओं को मौका मिले. परंतु इससे पार्टी के अंदर बुजुर्ग और युवा नेताओं में कलह शुरू हो गया. हालात यहां तक पहुंच गए कि ममता को राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नए सिरे से समिति गठित करनी पड़ी. पार्टी में दो ध्रुवीय विभाजन साफ दिखने लगा था. एक तरफ ममता के प्रति निष्ठा दिखाई.

motilal oswal Home Finance

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025। ईमेल: hfquery@motilaloaswal.com
CIN No.: U65923MH2013PLC248741

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (MOHFL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का अनुरोध किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह उचित विश्वास है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है:

स. क्र.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/ सह-आवेदक का नाम, गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और बकाया	अचल संपत्ति का विवरण
1.	खाता संख्या: LXSAG00316-170050958 एवं LXMOHOF1121-220608778 एवं LXMOHOF920-210553306 उधारकर्ता: शैलेन्द्र नेमा सह-उधारकर्ता: शारदा बाई नेमा	10.08.2025/रु. 15,36,593.00/- (रुपये पन्द्राह लाख छत्तीस हजार पाँच सौ तेरानवे मात्र)	मकान का हिस्सा अंदर आबादी, मकान संख्या 29, क्षेत्रफल 184 वर्ग फुट, मौजा-देवरी खास, तिलक वार्ड, देवरी, मुख्य बाजार के पीछे, तिलक वार्ड, देवरी, जिला सागर 470002, सागर, मध्य प्रदेश।

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि MOHFL एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो MOHFL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति(संपत्तियों) पर कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उसे हस्तांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। MOHFL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(यों) को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, MOHFL को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य MOHFL को देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत MOHFL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

ऋणकर्ता(कों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत ऋणकर्ता(कों) को MOHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणकर्ता(कों) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 19.08.2025

अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रजी संस्करण मान्य होगा